

सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय की अध्यक्षता में 7 अक्टूबर, 2026 को डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में आयोजित एलईडीसी की 5वीं बैठक का कार्यवृत्त

लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल (एलईडीसी) की 5वीं बैठक 7 अक्टूबर, 2026 को डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र (डीएआईसी), नई दिल्ली के हॉल संख्या 2 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री चंचल कुमार, की अध्यक्षता में आयोजित की गई ताकि भारत में लाइव इवेंट उद्योग के संवर्धन एवं विकास की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा तथा इस उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जा सके।

बैठक में केंद्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों तथा लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल (एलईडीसी) से संबंधित उद्योग जगत के हितधारकों ने सहभागिता की। प्रतिभागियों की सूची **अनुलग्नक-क** में संलग्न है।

2. श्री चंचल कुमार, सचिव, सूचना और प्रसारण ने अपने प्रारंभिक संबोधन में उल्लेख किया कि माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री द्वारा 14 माह से अधिक समय पूर्व गठित लाइव इवेंट डेवलपमेंट सेल ने अब तक चार बैठकों के माध्यम से केंद्र, राज्यों और उद्योग जगत को एक प्लेटफॉर्म पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में कॉन्सर्ट इकोनोमी की संभावनाओं तथा इसके विकास के लिए अनुकूल प्रणालियों और अवसंरचना की आवश्यकता पर दिए गए बल का उल्लेख करते हुए, यह रेखांकित किया कि सेल को मुख्यतः उपयुक्त आयोजन स्थलों के विकास के साथ-साथ लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से मंजूरी, वीजा, धन प्रेषण तथा संगीत लाइसेंसिंग से संबंधित प्रक्रियाओं को सुगम बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि लाइव इवेंट क्षेत्र के लिए प्रथम चरण के सुधार लागू किए जा चुके हैं तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से बाकी कार्यों को पूरा करने का आग्रह किया। इन कार्यों में नोडल अधिकारियों को नामित करना, आयोजन स्थलों को इस सेल से जोड़ना, मॉडल कार्यकारी आदेश (एमईओ) को अपनाना तथा लाइव इवेंट के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध लोक सेवा के रूप में अधिसूचित करना शामिल है।

3. उन्होंने बताया कि वेब्स 2027 का आयोजन 14 से 17 अक्टूबर, 2027 तक निर्धारित है और उद्योग जगत के सहयोग से दो पहलें शुरू करने का प्रस्ताव है। इनमें 'लाइव इवेंट में महिलाओं और दिव्यांगजनों की सुरक्षा हेतु समावेशिता संबंधी दिशानिर्देश' तथा 'ग्रीन कॉन्सर्ट प्रोटोकॉल' शामिल हैं।

4. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित लक्ष्यों को केवल महानगरों तक सीमित प्रयासों से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए टियर-II और टियर-III शहरों में उद्देश्य-विशिष्ट अवसंरचना की आवश्यकता है, जिसे केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और उद्योग जगत के संयुक्त प्रयासों से ही प्राप्त किया जा सकता है।

सचिव

5. श्री पृथुल कुमार, संयुक्त सचिव (प्रसारण एवं प्रशासन) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, ने अध्यक्ष के मार्गदर्शन के लिए उनका आभार व्यक्त किया तथा कार्यसूची के प्रत्येक बिंदु के संबंध में हुई प्रगति प्रस्तुत की। (प्रस्तुतिकरण की प्रति **अनुलग्नक-ख** के रूप में संलग्न है।) उन्होंने रेखांकित किया कि संगठित लाइव इवेंट क्षेत्र का बाजार मूल्य वर्ष 2025 में लगभग ₹145 अरब था, जिसके वर्ष 2028 तक बढ़कर ₹196 अरब होने का अनुमान है। इस क्षेत्र से एक करोड़ से अधिक लोगों की आजीविका को सहायता मिलने तथा इसका गुणक प्रभाव लगभग 4 होने का अनुमान है।

6. उन्होंने एलईडीसी की चौथी बैठक के बाद हुए निम्नलिखित जानकारी दी:

1. अंतरराष्ट्रीय कलाकारों को 5,00,000 अमेरिकी डॉलर से अधिक की अग्रिम धनराशि के प्रेषण के लिए बैंक गारंटी की अनिवार्यता से छूट देने के संबंध में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के अंतर्गत अधिसूचना।
2. अल्पकालिक प्रवास पर आने वाले विदेशी कलाकारों और उनके दल के सदस्यों के एफआरआरओ पंजीकरण के संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण।
3. लाइव इवेंट के आयोजन के लिए खेल स्थलों के उपयोग के संबंध में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एसओपी जारी करना।
4. लाइव इवेंट क्षेत्र में कौशल विकास पाठ्यक्रमों के संचालन के लिए भारतीय जनसंचार संस्थान, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल तथा इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के बीच समझौता ज्ञापन।

7. बैठक में कार्यसूची के विभिन्न बिंदुओं पर हुई चर्चा तथा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई बिंदु निर्धारित किए गए हैं:

1. लाइव इवेंट उद्योग के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल

(क) यह अवगत कराया गया कि लाइव इवेंट के लिए नोडल अधिकारियों के नामांकन के संबंध में शेष 7 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखे गए हैं।

(ख) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा उद्योग जगत के हितधारकों से निम्नलिखित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया:

1. एपीआई के माध्यम से **सभी विभागीय एवं स्थानीय लाइसेंसिंग प्रणालियों** को आईसीएच पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाए, ताकि राज्य पोर्टलों के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदक सीधे आईसीएच पोर्टल पर पहुँच सकें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एसओपी अपनाने तथा आईसीएच पोर्टल पर आयोजन स्थलों एवं संबंधित सेवाओं को जोड़ने की प्रक्रिया नवंबर, 2026 के अंत तक पूरी करने के लिए कहा गया।

II. लाइसेंस जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया केवल आईसीएच पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाए।

III. लाइव इवेंट के आयोजन स्थलों को आईसीएच पोर्टल से जोड़ना।

IV. संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सेवा प्रदायगी व्यवस्था के अंतर्गत लाइव इवेंट के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को समयबद्ध लोक सेवा के रूप में अधिसूचित किया जाए।

(क) संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से निम्नलिखित एकीकरण संबंधी कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया:

- I. नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) / नागर विमानन मंत्रालय: डीजीसीए ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को पत्र द्वारा अवगत कराया है कि केवल डिजिटलस्काई पोर्टल का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। नागर विमानन मंत्रालय से ड्रोन संबंधी अनुमतियों को आईसीएच पोर्टल के साथ पूर्णतः एकीकृत करने के लिए पुनः अनुरोध किया जाएगा। इस संबंध में नागर विमानन मंत्रालय एवं डीजीसीए को अलग-अलग पत्र भेजे जा सकते हैं।
- II. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण /संस्कृति मंत्रालय: एसआई का सहमत (सिस्टम फॉर अप्रवूल एट हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स ऑफ एसआई विथ ट्रांसपेरेन्सी) नामक एक अलग पोर्टल है। मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अक्टूबर, 2026 तक पूरी की जाएगी। इसके बाद नवंबर, 2026 तक आईसीएच पोर्टल के साथ एकीकरण तथा लाइव इवेंट के आयोजन हेतु एसआई के स्थलों को इस पोर्टल पर शामिल करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
- III. भारतीय खेल प्राधिकरण /युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय: एसआई के स्थलों पर लाइव इवेंट की बुकिंग एवं आयोजन के लिए एसओपी को 18 सितंबर, 2026 को अनुमोदित किया गया। एसआई ने अवगत कराया कि उसका पोर्टल डेढ़ माह में विकसित कर लिया जाएगा। एसआई को लाइव इवेंट से संबंधित अनुमतियों के लिए नवंबर, 2026 तक आईसीएच पोर्टल के साथ एकीकरण पूरा करने की सलाह दी गई।
- IV. उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग एवं संगीत लाइसेंसिंग एजेंसियाँ: डीपीआईआईटी ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को अवगत कराया है कि पोर्टल का तकनीकी प्रबंधन उसके कार्यक्षेत्र में नहीं आता है तथा यह उद्योग जगत के नेतृत्व में संचालित पोर्टल है।

प्रिद्धि

(ख) जहाँ भी तकनीकी रूप से संभव हो, एपीआई आधारित एकीकरण अपनाया जाए, ताकि आवेदकों को एक ही जानकारी बार-बार प्रस्तुत न करनी पड़े। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी आंतरिक कार्यप्रणाली बनाए रखने की छूट होगी, जबकि आवेदकों के लिए प्रदत्त प्रक्रिया निर्बाध और सुगम होनी चाहिए।

(ग) गृह मंत्रालय से अनुरोध किया गया कि लाइव इवेंट से जुड़े कलाकारों, प्रस्तुतकर्ताओं एवं अन्य दल के सदस्यों के लिए मौजूदा फिल्म वीजा सुविधा की तर्ज पर समूह-आधारित वीजा प्रक्रिया को सुगम बनाने हेतु एक तंत्र विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए। इस संबंध में गृह मंत्रालय को अलग से पत्र भेजा जाएगा।

(घ) उद्योग जगत को सलाह दी गई कि सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने के लिए केवल आईसीएच पोर्टल का ही उपयोग किया जाए।

2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लाइव इवेंट के लिए मॉडल कार्यकारी आदेश (एमईओ) का कार्यान्वयन

(1) यह अवगत कराया गया कि महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह द्वारा मॉडल कार्यकारी आदेश (एमईओ) अपनाया जा चुका है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा इसे अपनाना प्राथमिकता के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है।

(2) एलईडीसी के सदस्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमईओ को अपनाने की स्थिति निम्नानुसार है:

I. महाराष्ट्र: एमईओ अपनाया जा चुका है।

II. गोवा: एमईओ को अपनाने के लिए अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। एमईओ को अपनाने तथा राज्य की वेबसाइट को आईसीएच पोर्टल के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया नवंबर, 2026 के अंत तक पूरी कर ली जाएगी।

III. तमिलनाडु: एमईओ को अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा अंतिम अधिसूचना तैयार कर ली गई है। तथापि, बजट में संशोधन संबंधी अनुमोदन लंबित है। सचिव, सूचना और प्रसारण ने तमिलनाडु को 20 अक्टूबर, 2026 तक एमईओ अधिसूचित करने की सलाह दी।

IV. कर्नाटक: राज्य में सरकार में परिवर्तन के कारण एमईओ को अपनाने की प्रक्रिया 10 नवंबर, 2026 तक पूरी कर ली जाएगी।

V. दिल्ली: एमईओ के प्रावधानों पर भारतीय खेल प्राधिकरण सहित संबंधित हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित किया गया है। दिल्ली के मुख्य सचिव के साथ 9 सितंबर, 2026 को एक बैठक आयोजित की गई थी। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद एमईओ को 10 नवंबर, 2026 तक अपनाया जाएगा।

VI. असम: नोडल अधिकारी नामित किया जा चुका है। मॉडल कार्यकारी आदेश (एमईओ) को राज्य की इवेंट पर्यटन नीति के अनुरूप बनाया जा रहा है तथा इस पर उच्च स्तर पर विचार-विमर्श जारी है। संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए तैयार है और नवंबर, 2026 तक एमईओ को अपनाए जाने की संभावना है।

VII. पश्चिम बंगाल: एमईओ को 10 नवंबर, 2026 तक अपनाया जाना है।

VIII. उत्तर प्रदेश: एमईओ को नवंबर, 2026 तक अपनाया जाना है।

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई कि वे पोर्टल पर सभी सेवाओं एवं आयोजन स्थलों को शामिल करें, लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को सरल बनाने के प्रयास जारी रखें तथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर मॉडल कार्यकारी आदेश (एमईओ) को अपनाना सुनिश्चित करें।

(घ) महाराष्ट्र के सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय (डीजीआईपीआर) के निदेशक ने मॉडल कार्यकारी आदेश (एमईओ) को अपनाने के संबंध में एक प्रस्तुतीकरण दिया। (प्रस्तुतीकरण की प्रति अनुलग्नक-ग के रूप में संलग्न है।) इसके प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे:

- I. विभिन्न विभागों तथा उद्योग जगत के साथ परामर्श के बाद सितंबर, 2026 में एसओपी जारी की गई। इस रूपरेखा का नाम स्पाइस रखा गया है।
- II. राज्य स्तरीय इवेंट सुविधा सेल तथा डीजीआईपीआर के सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति की स्थापना।
- III. तीन चरणों वाली डिजिटल प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत राज्य की सिंगल विंडो मंजूरी प्रणाली (एसडब्ल्यूसीएस) को आईसीएच पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाना है।
- IV. कॉमन आवेदन फॉर्म, समेकित शुल्क, तत्काल प्रक्रिया, आयोजन से 24 घंटे पूर्व तैयारी संबंधी निरीक्षण तथा पूर्व-अनुमोदित आयोजन स्थलों पर बार-बार निरीक्षण से छूट का प्रावधान।

(ङ) इसके अतिरिक्त, अन्य केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभागों के साथ निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

I. कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई)

- 1) एमएसडीई ने लाइव इवेंट क्षेत्र के लिए पूर्व मान्यता (आरपीएल) के अंतर्गत

मिडि

कौशल समूहों के विकास के बारे में जानकारी दी।

- 2) एमएसडीई से लाइव मनोरंजन संबंधी कौशलों को राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा (एनएसक्यूएफ) में शामिल करने, समर्पित प्रशिक्षण केंद्रों एवं प्रमाणन निकायों की स्थापना करने तथा लाइव ईवेंट क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल विकसित करने हेतु व्यवस्थित प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया।

II. उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी)

1. एकल राष्ट्रीय संगीत लाइसेंस: डीपीआईआईटी निम्नलिखित प्रस्तावों की जांच कर सकता है।

- I. एक एकीकृत लाइसेंसिंग व्यवस्था, जिसके अंतर्गत अधिसूचित शुल्क दरों के आधार पर एक ही लाइसेंस से किसी कार्यक्रम को कवर किया जा सके तथा संबंधित अधिकारधारकों के बीच शुल्क का वितरण आंतरिक स्तर पर किया जाए।
- II. यह स्पष्ट किया जाए कि सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए लाइसेंस केवल पंजीकृत कॉपीराइट सोसायटियों द्वारा ही जारी किए जा सकते हैं।

III. शुल्क दर-सूचियों की समीक्षा एक नामित प्राधिकरण द्वारा किए जाना।

2. पूर्व में उल्लेख किए अनुसार, डीपीआईआईटी ने बताया कि यह पोर्टल उद्योग जगत के नेतृत्व में संचालित है।

3. पीपीएल ने कहा कि वसंत संगीत द्वार के माध्यम से अनेक लाइसेंस जारी करने से आयोजनकर्ताओं की मुख्य समस्या का समाधान नहीं होगा, क्योंकि अलग-अलग अधिकारधारकों को स्वतंत्र रूप से लाइसेंस जारी करने की अनुमति देने से कुल लाइसेंस शुल्क में वृद्धि हो सकती है। पीपीएल ने अंतरराष्ट्रीय कार्य पद्धतियों के अनुरूप केवल पंजीकृत कॉपीराइट सोसायटियों द्वारा लाइसेंस जारी किए जाने के मत का समर्थन किया।

4. ईईएमए ने सुझाव दिया कि इस विषय को अलग कार्यसूची बिंदु के रूप में लिया जाए। सचिव सूचना और प्रसारण ने संगीत लाइसेंसिंग से संबंधित हितधारकों को आपस में विचार-विमर्श कर सहमति बनाने तथा तत्पश्चात मंत्रालय के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने की सलाह दी।

III. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी)

1. एमओईएफसीसी ने बताया कि रात्रि 10 बजे के बाद आयोजन की अनुमति देने के लिए मौजूदा कानूनी प्रावधानों में संशोधन नहीं किया जा सकता। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अंतर्गत अधिसूचित मनोरंजन क्षेत्रों के गठन के प्रस्ताव सहित इस विषय को पुनः एमओईएफसीसी के समक्ष

उठाया जाना है।

IV. आर्थिक कार्य विभाग

- 1) डीईए ने सूचित किया कि बुनियादी ढांचा उप-क्षेत्रों के वित्त पोषण की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में लाइव इवेंट और प्रदर्शन स्थलों को शामिल करने के लिए संबंधित मंत्रालय से एक प्रस्ताव की आवश्यकता होगी, जिसकी रंगराजन समिति के मानदंडों के आधार पर विधिवत जांच की जाएगी, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित और उचित सीमा निर्धारित होगी।
- 2) इसके बाद सचिव (आर्थिक मामले) की अध्यक्षता वाले संस्थागत तंत्र द्वारा प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है।

3. पूर्व-स्वीकृत स्थान

1. एसआई और एसआई आईसीएच पोर्टल पर शामिल किए जाने वाले स्थानों की पहचान करेंगे, ताकि कार्यक्रम आयोजकों को प्रत्येक कार्यक्रम के लिए स्थल-स्तर की लाइसेंसिंग और अनुमति की उसी प्रक्रिया से बार-बार गुजरना न पड़े।
2. राज्य और संघ राज्य क्षेत्र उपयुक्त स्थलों की पहचान करें और उनकी क्षमता, स्थान और सुविधाओं का मानचित्रण करें, जिन्हें पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
3. उद्योग से अनुरोध किया गया था कि वे दो माह के भीतर आईसीएच पोर्टल पर ऑनबोर्डिंग के लिए प्राइवेट स्थानों का प्रस्ताव दें। शुरुआत में स्थानों की ऑनबोर्डिंग के लिए 5,000+ की न्यूनतम क्षमता इंगित की गई थी।

4. ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड स्थल विकास

- क) यह नोट किया गया कि भारत में सीमित संख्या में ऐसे स्थान हैं जो लाइव इवेंट आयोजित कर सकते हैं
- ख) यह चिन्हित किया गया कि उद्योग के विकास के लिए केवल बड़े

प्रति

स्थानों की ही नहीं बल्कि छोटे स्थानों की भी आवश्यकता है।

ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था कि वे लाइव इवेंट के लिए उद्देश्य-निर्मित अवसंरचना की पहचान करें तथा उसे विकसित करें, और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, उद्योग हितधारकों और एआईसीटीई सदस्यों को साझा किए गए मसौदे पर औपचारिक प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए कहा गया था।

घ) वीजीएफ योजना के माध्यम से केंद्र की संभावित सहायता पर भी चर्चा की गई।

5. आईआईएमसी में लाइव इवेंट क्षेत्र के लिए कौशल पाठ्यक्रम पर प्रस्तुति (लाइव इवेंट स्किलिंग कमेटी द्वारा) (अनुलग्नक घ के रूप में प्रस्तुति की प्रतिलिपि संलग्न)

क) यह सूचित किया गया कि एक डिप्लोमा को एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित किया गया है और उद्योग द्वारा मान्य किया गया है।

ख) सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सलाह दी कि:

i. पाठ्यक्रम की विषय-वस्तु उद्योग की मांगों के अनुरूप होनी चाहिए, और कौशल समिति को एक स्थायी समिति के रूप में कार्य करना चाहिए।

ii. एआईसीटीई के साथ एडवांस डिप्लोमा विकसित किया जा सकता है, और अगले एक से दो वर्षों में डिग्री पाठ्यक्रमों पर भी विचार किया जा सकता है।

iii. अनुमोदन में आने वाली समस्याओं की पहचान की जाए और उन्हें यूजीसी और एआईसीटीई के समक्ष उठाया जाए।

ग) आईआईएमसी के कुलपति ने उल्लेख किया कि आईआईएमसी के क्षेत्रीय परिसरों का उपयोग पाठ्यक्रमों के लिए किया जाएगा, इस प्रकार एक बहुभाषी दृष्टिकोण को सक्षम किया जाएगा।

घ) आईआईएमसी पाठ्यक्रमों को डिजाइन करते समय ईईएमए द्वारा सुझाए गए शब्दावली के लिए टेम्पलेट का उपयोग करने पर विचार करेगा।

ङ) राज्य और संघ राज्य क्षेत्र अपने संबंधित कौशल संस्थानों के माध्यम से आईआईएमसी द्वारा कौशल मॉड्यूल को अपनाने की संभावना तलाश सकते हैं।

1. वेक्स 2027 14 से 17 अक्टूबर 2027 तक आयोजित किया जाएगा
2. लाइव इवेंट्स में महिलाओं और दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए समावेशिता दिशानिर्देश और ग्रीन कॉन्सर्ट प्रोटोकॉल, उद्योग के सहयोग से तैयार किए जाएंगे।
3. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा कि दोनों पहलों के विकास का नेतृत्व ईईएमए द्वारा किया जाना चाहिए। उनके विकास और कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए विशिष्ट समितियों का गठन किया जाएगा।
4. उद्योग निकाय एसोचैम ने "ग्रीन कॉन्सर्ट प्रोटोकॉल" दस्तावेज़ के लिए काम करने की इच्छा व्यक्त की, जबकि फिक्की, एमईएससी और पीएचडीसीसीआई ने "लाइव इवेंट्स में महिलाओं और दिव्यांगजनों की सुरक्षा के लिए समावेशिता दिशानिर्देश" के गठन की दिशा में काम करने की इच्छा व्यक्त की।
5. एमईएससी ने वेक्स 2027 में एक कौशल पैवेलियन स्थापित करने की भी इच्छा व्यक्त की।
6. वेक्स 2027 में "कल्चरल एंड कॉन्सर्ट्स" पिलर के तहत विभिन्न खंडों के आयोजन के लिए उद्योग के हितधारकों का समर्थन मांगा गया।
8. यह उल्लेख किया गया कि आईसीएच पोर्टल के संचालन से परिचित होने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए क्षमता निर्माण कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी।
9. संयुक्त सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पहल के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख मुद्दों पर उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और निदेशों के लिए अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। सदस्यों ने आश्वासन दिया कि चिन्हित कार्यों को आगे बढ़ाते समय और उनके समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करते समय प्रदान किए गए मार्गदर्शन पर विधिवत विचार किया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और उद्योग हितधारकों के प्रतिनिधियों को उनकी भागीदारी और मूल्यवान सुझावों के लिए धन्यवाद दिया और इस बात पर जोर दिया कि प्रस्तावित उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी हितधारकों के बीच निरंतर समन्वय आवश्यक होगा।

मिडि

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

अनुलग्नक क

भारत सरकार

1. श्री चंचल कुमार आईएस, सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (अध्यक्ष, एलईडीसी)
2. श्री पृथुल कुमार, संयुक्त सचिव (प्रसारण एवं प्रशासन), सूचना और प्रसारण मंत्रालय
3. डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़, कुलपति, आईआईएमसी
4. श्री ब्रजेश गोद्रा, उप सचिव (बीई एवं बीसी -IV), सूचना और प्रसारण मंत्रालय (सदस्य सचिव, एलईडीसी)
5. श्री मिहिर कुमार झा, अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
6. श्री महेश कुमार, सीएमसी, सूचना और प्रसारण मंत्रालय
7. सुश्री सीमा जोशी, निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय
8. श्री एस.के. सिंह, अवर सचिव, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय
9. श्री आर.डी. मीणा, निदेशक, गृह मंत्रालय
10. डॉ. संजय कुमार मंजुल, अपर महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, संस्कृति मंत्रालय
11. श्री जुल्फेकार अली, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण
12. श्री मो. जुबेर, उप सचिव, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
13. श्री वी.एस. अरविंद, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
14. श्री संजय कुमार, डीपीआईटी
15. सुश्री शिवालिका बख्शी, कानूनी सलाहकार, डीपीआईआईटी, वाणिज्य

और उद्योग मंत्रालय

राज्य सरकारें

1. श्री जे. मंजूनाथ, सचिव, डीआईपीआर, कर्नाटक
2. श्री मानस मंडल, संयुक्त सचिव (फिल्म), पश्चिम बंगाल सरकार
3. श्री हेमराज बगुल, निदेशक, डीजीआईपीआर, महाराष्ट्र
4. श्री के. तमिलसेल्वराजन, अपर निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, तमिलनाडु सरकार
5. श्री आर. राजेश कन्नन, सूचना अधिकारी, तमिलनाडु सरकार, नई दिल्ली
6. श्री अनिरुध कुमार मिश्रा, अपर निदेशक, डीआईपीआर, उत्तर प्रदेश
7. श्री सुनील कनौजिया, सहायक निदेशक (सूचना), डीआईपीआर, उत्तर प्रदेश
8. श्री मृणाल वाल्के, महाप्रबंधक, एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा, गोवा सरकार
9. डॉ. पार्थ प्रतिम दास, असम पर्यटन, असम
10. श्री मनीषा बख्शी, दिल्ली पर्यटन (डीटीटीडीसी), दिल्ली
11. सुश्री प्रियंका गौर, डीटीटीडीसी, दिल्ली

उद्योग

1. सुश्री प्रीति खन्ना, कार्यकारी निदेशक, ईईएमए
2. श्री नवीन गुप्ता, एसपीएलबीए, ईईएमए
3. श्री संजीव पसरीचा, ईएमए
4. श्री रामकुमार विजयन, प्रमुख - पर्यटन, मीडिया और मनोरंजन, एसोचैम
5. सुश्री सोनल माथुर, निदेशक - मीडिया और मनोरंजन, फिक्की
6. सुश्री मंशा विज, फिक्की
7. डॉ. सुभाष मेहता, उप सचिव, पीएचडीसीसीआई
8. एमएस. लावण्या उपाध्याय कार्यकारी अधिकारी, पीएचडीसीसीआई
9. सुश्री पूजा अरोड़ा, सीओओ, मीडिया और मनोरंजन कौशल परिषद (एमईएससी)
10. श्री जी.बी. आयर, सीईओ, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (पीपीएल)
11. श्री शैलेश कृपाल, महाप्रबंधक, फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड (पीपीएल)
12. श्री वरुण शर्मा, आई.पी.आर.एस.

मिहिर

13. श्री जेनिल शाह, महासचिव, आईएमआई
14. श्री आशीष आर. दीक्षित, आरएमपीएल
15. श्री विवेक कुमार, बुक माई शो
16. सुश्री दामिनी भल्ला, जिला (वीसी)

अन्य

1. श्री सौमित्र साहू, प्रमुख, इंडिया सिने हब, एनएफडीसी
2. श्री तन्मय शंकर, प्रमुख (डिजिटल ग्रोथ और टेक्नोलॉजी), एनएफडीसी
3. सुश्री प्राजक्ता सपाते, उप प्रमुख, इंडिया सिने हब, एनएफडीसी
4. सुश्री पायल बोस, संचालन प्रबंधक, इंडिया सिने हब, एनएफडीसी
5. प्रोफेसर राकेश गोस्वामी, आईआईएमसी, नई दिल्ली
6. श्री सनी एस. पराशर, परियोजना प्रबंधक, ईवाई
7. श्री आयुष गोयल, परियोजना सलाहकार, ईवाई
8. श्री अभिनव पांडे एस, परियोजना सलाहकार, ईवाई
9. श्री नचिकेत डी. शिरोलकर, परियोजना सलाहकार, ईवाई
10. श्री अभय कुमार, परियोजना प्रबंधक, यूनीकॉप्स
11. श्री विक्रान्त गौतम, वरिष्ठ व्यापार विश्लेषक, यूनीकॉप्स

5TH MEETING • 07 OCTOBER 2026

Live Events Development Cell (LEDC)

Promotion and development of India's live events industry

Agenda presentation for the 5th meeting of the Cell, chaired by Secretary, Ministry of Information & Broadcasting



Government of India
**Ministry of
Information and Broadcasting**





80TH INDEPENDENCE DAY • RED FORT • 15 AUGUST 2026

“

The concert economy is growing rapidly and has tremendous appeal for the country's youth. **Artists from across the world want to perform a concert on Indian soil** at some point. This is a huge opportunity, and **we must create the systems and infrastructure needed to mobilise this opportunity.**

Shri Narendra Modi

Hon'ble Prime Minister of India

Live events: A High-impact Economic Multiplier

India's organised live events sector today, and the Roadmap target for 2030

₹145 bn

Organised live events sector in 2025, across ~34,000 events



₹196 bn

Projected sector size by 2028



1 crore+

Livelihoods supported by the sector



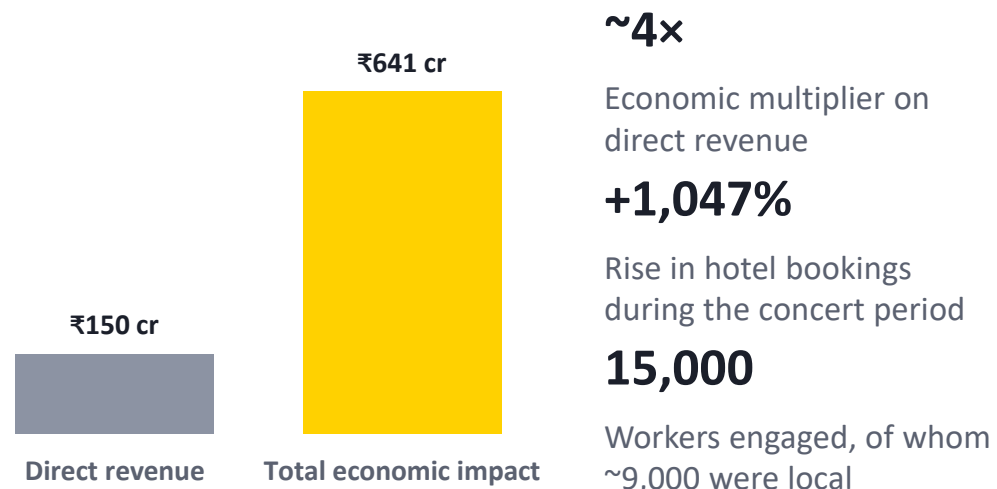
2× | 15–20 mn

Roadmap 2030: double the sector; 15–20 million direct and ancillary jobs



Coldplay concerts, Ahmedabad (January 2025)

Total economic impact vs direct revenue, ₹ crore



Other marquee events, 2025

Dil-Luminati Tour

14 Shows · 13 Cities · Est. total impact ₹943 cr+

Post Malone, Guwahati

1 Concert · Est. total impact ₹43 cr+
· 53% Visitors from outside Guwahati

LEDC: Whole-of-Government platform for the Live Events Sector

Chairperson: Secretary, Ministry of Information & Broadcasting · Member Secretary: DS (BAE & BC-IV), MIB



14

Central Ministries and
Departments



10

States and Union Territories



21

Industry bodies and key players

From the Odisha Conclave to the 5th LEDC



First-generation reforms



Model Executive Order, 2026

Uniform, time-bound licensing framework for adoption by States/UTs

IN PLACE



Single window on India Cine Hub

One portal for all live event clearances

IN PLACE



Department-specific facilitations

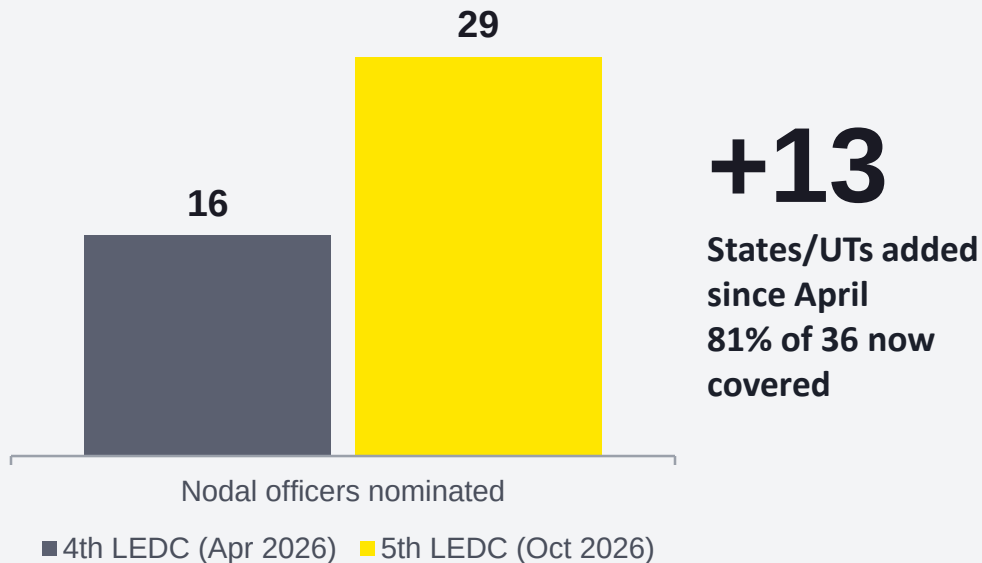
ASI & SAI venue SOPs, RBI remittance relaxation, FCRA rationalisation (MHA) and others

BEING WORKED UPON

Progress since the 4th LEDC (30 April 2026)

Portal readiness has moved. Four department-level facilitations have been secured

States/UTs on the ICH Live Events Portal Nodal officers nominated (of 36 States/UTs)



Model Executive Order adopted by 5 States/UTs



FEMA notification

NOTIFIED

Bank guarantee requirement waived for advance remittances above USD 500,000 to international artists



FRRO re-registration (MHA)

CLARIFIED

180-day threshold clarified; re-registration for short-term stays by foreign performers streamlined. Performer's visa under consideration



SAI stadia booking & event SOP

PUBLISHED 18 SEP 2026

Opens SAI venues to live events; Major Dhyan Chand National Stadium onboarding under way



Skilling MoUs (IIMC)

SIGNED 29 SEP 2026

IIMC–EEMA and IIMC–MESC MoUs for live event skilling courses



Events beyond 10 PM (MoEFCC)

CLARIFIED

Not possible under the present legal framework; precinct-based alternative proposed under Agenda 2

Agenda for the 5th LEDC

Six items, two presentations by participants, followed by an open forum

1



Single Window Clearances Portal

Implementation status: States/UTs, Central Ministries and industry

2



Model SOP for Live Events (MEO)

Adoption by States/UTs; Central Ministry actions; proposals on music licensing and entertainment precincts

3



Pre-approved venues

SAI and ASI SOPs; venue onboarding on the ICH portal

4



Brownfield & greenfield venues

Feedback on the draft framework; purpose-built venue infrastructure and financing.

5



Live event skilling curriculum at IIMC

MoU status, courses and adoption by States/UTs

6



Launches proposed for WAVES 2027

Inclusivity Guidelines; Green Concert Protocol – to be prepared with industry support

ICH Live Events Portal: where we stand

Nodal officers, mapping and integrations with Central systems

29 / 36

States/UTs have
nominated a nodal officer

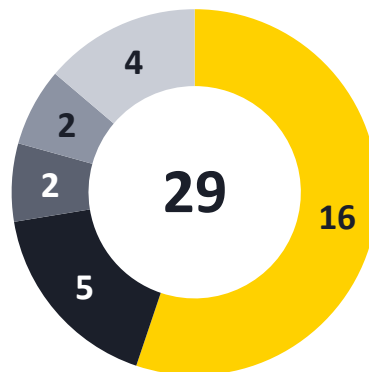
7

States/UTs yet to nominate:

- Andhra Pradesh (AP)
- Chhattisgarh
- Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu (DNH&DD)
- Jharkhand
- Ladakh
- Mizoram
- Telangana

Nodal officers by department

29 nominations across 36 States/UTs



Information & Public Relations	16
Tourism	5
Art & Culture	2
Information & Cultural Affairs	2
Others (one each): Industry & Commerce, Local Administration, State Information Centre, Home	4

Integrations with Central systems

Sought from Central Ministries; all in progress



DGCA / Ministry of Civil Aviation

IN PROGRESS

DigitalSky integration with ICH for Drone Permissions



ASI / Ministry of Culture

IN PROGRESS

Venue onboarding and Portal Integration to commence after ratification of SOP



SAI / Ministry of Youth Affairs & Sports

IN PROGRESS

Venue Onboarding to be completed and integration of their application form fields within ICH Portal



DPIIT & music licensing agencies

IN PROGRESS

VasantSangeetDwar portal integration with ICH

State/UT readiness at a glance

MEO adoption · Nodal Officer Nominated

#	State / UT	MEO Adopted	Nodal Officer
1	Andaman & Nicobar Islands	✓	✓
2	Andhra Pradesh	—	—
3	Arunachal Pradesh	✓	✓
4	Assam	—	✓
5	Bihar	—	✓
6	Chandigarh	—	✓
7	Chhattisgarh	—	—
8	Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu	—	—
9	Delhi	—	✓
10	Goa	—	✓
11	Gujarat	—	✓
12	Haryana	—	✓
13	Himachal Pradesh	—	✓
14	Jammu & Kashmir	—	✓
15	Jharkhand	—	—
16	Karnataka	—	✓
17	Kerala	—	✓
18	Ladakh	—	—

#	State / UT	MEO Adopted	Nodal Officer
19	Lakshadweep	—	✓
20	Madhya Pradesh	—	✓
21	Maharashtra	✓	✓
22	Manipur	—	✓
23	Meghalaya	—	✓
24	Mizoram	—	—
25	Nagaland	—	✓
26	Odisha	—	✓
27	Puducherry	—	✓
28	Punjab	—	✓
29	Rajasthan	—	✓
30	Sikkim	—	✓
31	Tamil Nadu	—	✓
32	Telangana	—	—
33	Tripura	✓	✓
34	Uttar Pradesh	—	✓
35	Uttarakhand	✓	✓
36	West Bengal	—	✓

■ Completed
 ■ Pending

MEO adopted: 5 · Nodal officer nominated: 29

Single Window: Actions Requested

For the portal to work as the sole channel, each stakeholder has defined steps



States / UTs

1. **Designate a Nodal Officer** for live events licensing facilitation
2. **Nominate departmental authorised officers** across all concerned authorities
3. **Integrate departmental and local licensing systems** with the ICH portal
4. **Route the complete licence lifecycle** through the ICH portal only
5. **Onboard live event venues** on the ICH portal
6. **Notify live event licensing as a time-bound public service** under the State/UT service delivery framework



Central Ministries

1. **DGCA / MoCA:** integrate DigitalSky with ICH for drone permissions
2. **ASI / Ministry of Culture:** Ratify the SOP to enable integration of protected monuments and sites permitted for live events
3. **SAI / MoYAS:** Identify and integrate venues on the ICH Portal. Integration of application form fields on ICH Portal to be initiated
4. **DPIIT & music licensing agencies:** Integration of the VasantSangeetDwar portal with ICH Portal



Industry

1. **Use the ICH portal exclusively** for seeking live event permissions
2. **Register private venues** on the portal with up-to-date safety and statutory certifications
3. **Flag process gaps** to the State nodal officer and the LEDC secretariat



Objective: Every live event permission in India – State, local and Central – applied for, tracked and granted through the ICH portal alone, within notified timelines

Model Executive Order, 2026: adopted by 5 of 36 States/UTs

A State-adoptable framework replacing fragmented licensing with a harmonised, digital, time-bound system

Adoption Status



Adopted the MEO

- 1 Maharashtra (LEDC member State)
- 2 Arunachal Pradesh
- 3 Tripura
- 4 Uttarakhand
- 5 Andaman & Nicobar Islands

Follow-up with States/UTs

- **13 Mar 2026**
MEO circulated to States/UTs for adoption
- **16 Apr 2026**
Secretary, MIB chairs VC on adoption / contextualisation of the MEO
- **31 May 2026**
45-day target for States/UTs to adopt or customise the MEO
- **16 Jun 2026**
Review VC: most States/UTs indicated adoption within 30 days
- **15 Jul 2026**
JS (Broadcasting), MIB - review VC; States/UTs urged to adopt
- **25 AUG 2026**
MEETING WITH STATE DIPR CHAIRED BY SIB: most States/UTs indicated adoption within 30 days

What the MEO delivers

-  **Single-window mechanism**
With institutional accountability
-  **Standard licence conditions**
Timelines, tatkal processing, digital fee payment
-  **Rationalised permissions**
Redundant NOCs removed; six mandatory licences tracked digitally
-  **State Nodal Officer**
Single point of contact, supported by officers of all line departments
-  **Time-bound public service**
Licensing notified under the state service delivery framework
-  **Monitoring Committee**
Delays auto-referred; time-bound decisions; deemed approval

PRESENTATION BY A PARTICIPANT



Government of Maharashtra

The only LEDC member State to have adopted the Model Executive Order

Adoption of the Model Executive Order, 2026: Maharashtra's experience

AGENDA ITEM 2(B)

Central Ministries: status against actions sought at the 4th LEDC

Nine Ministries/Departments; three proposals for today's discussion follow

Ministry of Youth Affairs & Sports / SAI

SOP issued

Sports arenas for live events; venue utilisation framework; pre-approved venues

Status: Stadia booking and event SOP published on 18 Sep 2026; Major Dhyan Chand National Stadium onboarding under way



Ministry of Culture / ASI

SOP Pending

Heritage venues for live events; operational framework; pre-approved list

Status: SOP for live events at protected monuments to be issued; onboarding of permitted monuments on ICH to follow



Ministry of Home Affairs

Partly done

Group Visa for Artists & Crews (Film Visa Category), Customs Duty Exemption for Show Equipment, and FRRO Facilitation

Status: FRRO re-registration for short-term stays streamlined; Group visa provisions to be taken forward

Ministry of Skill Development & Entrepreneurship

Response awaited

Live entertainment skills in NSQF; training centres and certification bodies; apprenticeships

Status: Response Awaited



Ministry of Tourism

Response awaited

Promote India as a global hub for event-based tourism; incentives, funding and PPP support for venues

Status: Response awaited



Ministry of Finance & MSME

Response awaited

GST rationalisation, CSR alignment; infrastructure financing (VGF, blended finance); MSME recognition

Status: Response awaited



DPIIT

Proposal tabled

Unified online music licensing; copyright rationalisation; event IPs as recognised enterprises

Status: VasantSangeetDwar-ICH integration under discussion; proposal for one national music licence tabled today



MoEFCC

Proposal tabled

Feasibility of live events running beyond 10 PM

Status: Not possible in the present legal framework; Proposal for Notified Entertainment Precincts to be considered



Dept. of Economic Affairs

Response awaited

Relaxation of the cap on foreign remittances for payments to international artists

Status: Referred to the FEMA Division; SIB to write to DEA again

Proposal for DPIIT: one national music licence for live events

Convert an open-ended legal exposure into a predictable budget line, at nil cost to the exchequer



The problem today

- Event organisers face overlapping demands from multiple societies and entities for the same event
- Recurring litigation on who is entitled to issue licences and set tariffs
- Open-ended copyright exposure makes event budgeting unpredictable and deters investors



International practice



United Kingdom

PPL and PRS for Music operate jointly through PPL PRS Ltd, issuing a single licence, TheMusicLicence



Canada

Entandem, established by SOCAN and Re:Sound, administers music license



Proposal: DPIIT may

- 1 A single license with notified tariffs covers an event
- 2 Back-end apportionment of licence fees among eligible rights holders
- 3 Licensing only by Registered Copyright Societies
- 4 Enable independent review of tariff schedules



Expected outcome: predictable licensing costs, fewer disputes and stronger investor confidence – the single largest gain in investor confidence available at nil cost to the exchequer

Proposal for MoEFCC: notified entertainment precincts

Noise standards that attach to a notified precinct rather than to each individual event



Present position

- Loudspeaker and public event restrictions apply after 10:00 PM
- Rule 5(3), Noise Pollution Rules, 2000 already lets State Governments permit loudspeakers between 10 PM to 12 AM on up to 15 days a year
- MoEFCC: extending events beyond 10 PM is not possible in the present legal framework



International practice



New South Wales, Australia

Vibrancy Reforms, 2023–25

- Precinct-wide sound standards and trading hours for Special Entertainment Precincts
- Precinct plans override venue-specific conditions
- Implementation supported by the 24-Hour Economy Commissioner



Proposal: MoEFCC may

- 1 Create a category of Notified Entertainment Precincts under the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000
- 2 Apply ambient noise standards to the precinct, than each event, with monitoring at precinct boundary
- 3 States/UTs may propose precincts with defined boundaries, operating hours and sound limits
- 4 Locate precincts at a safe distance from silence zones

Pre-approved venues: SOPs in place, onboarding to follow

Organisers should not repeat venue-level licensing for every event at a pre-approved venue



ASI venues

SOP to be issued

224 Protected monuments and sites

Onboarding of permitted venues to be initiated after ratification of SOP



SAI venues

SOP PUBLISHED 18 SEP 2026

2 Stadia onboarded: JLN stadium and IG stadium, New Delhi

Major Dhyan Chand National Stadium onboarding under way; Integration with ICH Portal to be initiated



Private venues

ONBOARDING UNDER WAY

2 Venues in process: CIDCO ground, Navi Mumbai and NESCO Centre, Mumbai

Private venues register on the ICH portal and keep certifications current

How pre-approval works



Government venues

- SAI and ASI to pre-approve major venues so that organisers need not go through venue-level licensing for each event
- State Governments and Government-owned or aided entities may notify pre-approved venues, based on prescribed safety, fire, electrical and crowd-management norms



Private venues

- Register on the ICH portal, keeping safety and statutory certifications updated
- Provide approved layouts and maintain a live events calendar on the portal

Purpose-built venues: from framework to financing

India has very few purpose-built venues in the 15,000–20,000 capacity range



Where we are

- **Draft greenfield venue development framework** circulated with LEDC Stakeholders
- Formal feedback awaited
- **Dates of correspondence: 5th May 2026, 25th August 2026, 5th October 2026**
- **Key Observation:** Most large events in India are staged at sports stadia or open grounds, with conflicts of scheduling, acoustics and cost of setup
- **Venue development is in practice a State/UT subject:** Land, Municipal Permissions and policing rest with States

FEEDBACK AWAITED



International practice

Saudi Arabia and Republic of Korea

Purpose-built arena programmes pursued as state-supported infrastructure

Singapore

Sports Hub developed on PPP lines; now known as The Kallang (Brownfield Venue Development)

United Kingdom

£1 levy on tickets of large-capacity shows (adopted by the Royal Albert Hall in 2025), Administered by an industry trust to sustain smaller venues (After ~175 towns stopped receiving touring shows)



Proposals

- 1 **States and UTs** to identify and develop purpose-built venue infrastructure for live events
- 2 **DEA may include dedicated live event and performance venues** above a threshold capacity in the **Harmonised Master List of Infrastructure Sub-sectors – as done for sports infrastructure in 2020**, unlocking infrastructure lending norms, longer loan tenures, InvIT eligibility and external commercial borrowing
- 3 **Central support through the VGF Scheme:** Up to 30% of total project cost, as allowed for social infrastructure sub-sectors

PRESENTATION BY A PARTICIPANT



Live Event Skilling Committee

Chaired by the Vice Chancellor, Indian Institute of Mass Communication (IIMC)

Skilling curriculum for the live events sector at IIMC: progress report

AGENDA ITEM 5

WAVES 2027: Two Launches to be Prepared with LEDC Support

LAUNCH 01



Inclusivity Guidelines

Safety of women and Divyangjan at live events and concerts · 16 indicative measures



Safety of women artists and attendees

- Gender-responsive venue risk assessment
- Well-lit entry, exit, parking and last-mile zones
- Trained women security staff and help desks
- Secure, access-controlled backstage and changing rooms
- Confidential reporting and rapid-response protocols
- Safe crowd management at entry and dispersal
- Sensitisation of organisers, staff, crew and vendors
- Zero tolerance on harassment and misconduct



Safety and accessibility for Divyangjan

- Accessibility audit of venues and infrastructure
- Barrier-free entry, seating, stages and backstage
- Accessible toilets, parking and viewing platforms
- Accessible ticketing and advance facility information
- Sign-language, captioning and assistive services
- Trained accessibility staff and assistance desks
- Inclusive emergency alerts and evacuation plans
- Accessible feedback and grievance redressal

LAUNCH 02



Green Concert Protocol

Sustainability standards for all concerts and cultural events · nine pillars

- 1 Circular and reusable stage infrastructure
- 2 Low-plastic backstage operations
- 3 Digital-first event operations
- 4 Public transport and shared mobility
- 5 Carbon measurement and reduction
- 6 Waste prevention and segregation
- 7 Sustainable and local procurement
- 8 Clean energy and resource efficiency
- 9 Green governance and accountability

WAVES 2027 Cultural & Concerts segment: Nine Proposed Initiatives

Proposed alongside the two launches; partner agencies indicative



WAVES Kala Sanjeevani

Promoting rare and endangered art forms

Partners: Ministry of Culture, ICCR



WAVES Guru–Shishya Sessions

Recitals and interactions showcasing the guru–shishya tradition

Partners: Ministry of Culture



Cultural Leaders Roundtable / Global South Cultural Forum

Cultural diplomacy, creative economy and digital heritage

Partners: Ministry of Culture, Ministry of External Affairs



Co-located city cultural events

Concerts, theatre and bhakti events across the city; City Cultural Passport

Partners: Industry leaders, Government of Maharashtra



Artist Rights and Royalties Clinic

Help desks and workshops on contracts, copyright, royalties and distribution

Partners: IPRS, PPL, IMI, Copyright Office, SNA, platforms



Bharat & the World

State/UT performing traditions and performances from across the world

Partners: States/UTs, foreign missions



AI × Cultural Performance Lab

Responsible AI in music, scenography, translation and heritage reconstruction

Partners: MeitY, IndiaAI Mission, NASSCOM, SNA, industry bodies



Gala Premiere: Red Carpet

Announcement of upcoming national and international tours in India

Partners: Ticketing and live entertainment platforms



WAVES Cultural Archive (OTT)

Digital archive of performances, interviews, instruments, costumes and oral histories

Partners: Prasar Bharati, NFDC, Sangeet Natak Akademi

OPEN FORUM



Remarks from participants

States/UTs, Central Ministries and Departments, industry bodies and key players

Issues, feedback and suggestions on the agenda items and the way forward

AFTER AGENDA ITEM 6

Chair invites remarks from the floor

Any other matter with the permission of the Chair

Summary of actions sought from the 5th LEDC

For confirmation in the record of discussions



States / UTs

- ✓ Adopt or contextualise the MEO (31 States/UTs in process)
- ✓ Nominate nodal and departmental officers (7 yet to nominate)
- ✓ Integrate departmental and local systems; route the full license lifecycle through ICH only
- ✓ Notify live event licensing as a time-bound public service
- ✓ Onboard venues; identify sites for purpose-built venues
- ✓ Send formal feedback on the greenfield venue framework
- ✓ Adopt IIMC skilling modules through State skilling institutions



Central Ministries

- ✓ DGCA, ASI, SAI, DPIIT: Complete integrations with the ICH portal
- ✓ DPIIT: One national music licence with notified tariffs
- ✓ MoEFCC: Notified entertainment precincts under the Noise Pollution Rules, 2000
- ✓ DEA: Remittance cap relaxation; live event venues in the Harmonised Master List
- ✓ MoF & MSME: VGF support, GST/CSR measures, MSME recognition
- ✓ MHA: Group visa for artists and crews · MSDE: NSQF integration · MoT: event-tourism promotion



Industry

- ✓ Use the ICH portal exclusively for permissions
- ✓ Register private venues and keep certifications current
- ✓ Co-develop the Inclusivity Guidelines and the Green Concert Protocol for launch at WAVES 2027
- ✓ Provide feedback on the greenfield venue framework
- ✓ Support the IIMC skilling courses with industry placements and faculty

Thank you

Live Events Development Cell · Ministry of Information & Broadcasting, Government of India

Secretariat: DS (BAE & BC-IV), Member Secretary, LEDC · India Cine Hub Live Events Portal



Government of India

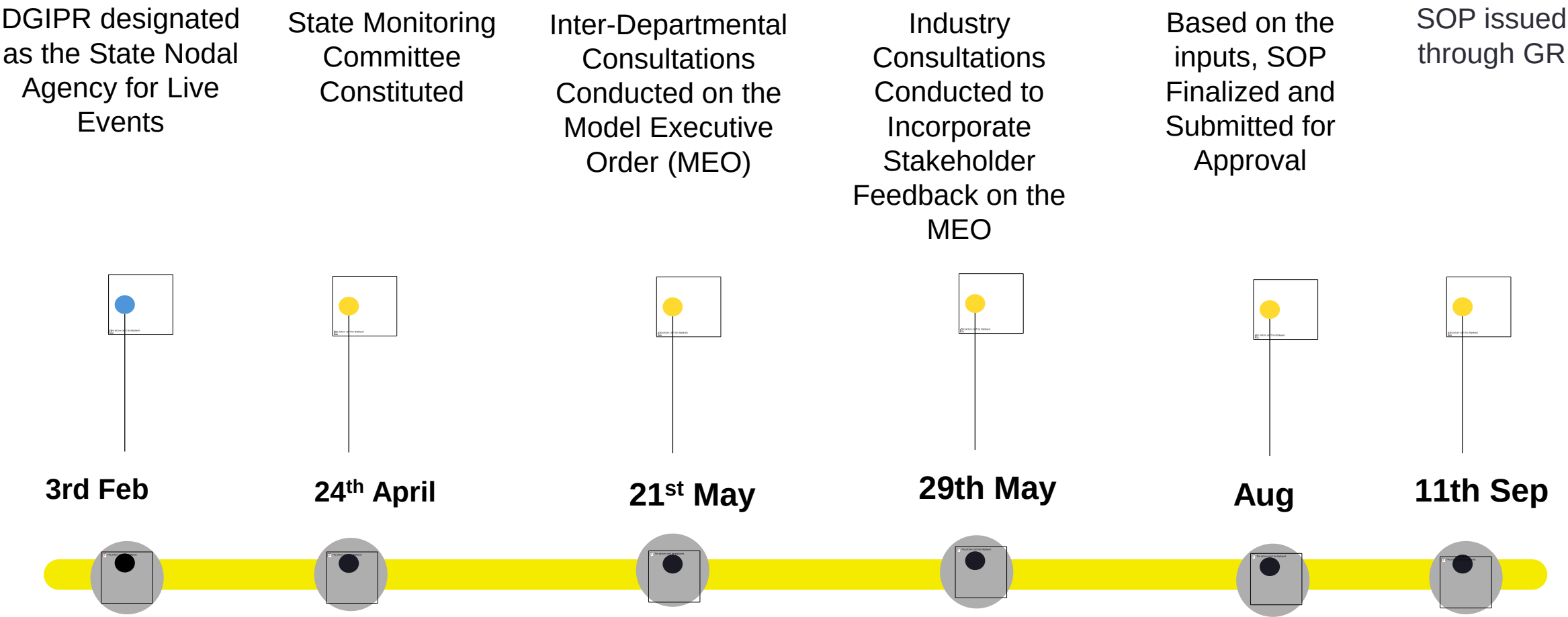
**Ministry of
Information and Broadcasting**



**Adoption of the Model
Executive Order and
Development of the State
SOP for Live Events**



Adoption of the MEO and Development of the State SOP Enabled Key Initiatives





STATE EXECUTIVE
ORDER IS TITLED

SPLICE

Streamlining Permissions and Licensing for Integrated Comprehensive Events

STRATEGIC OBJECTIVES **Eight priorities, organised around four outcomes**

01 Faster, simpler approvals

- Streamline event approvals through a Single Window Clearance System
- Reduce approval timelines and procedural duplication

02 Consistent regulation

- Standardise regulatory and compliance processes
- Promote a predictable and investor-friendly ecosystem

03 Investment & destination

- Attract domestic and international investments
- Position Maharashtra as a premier live events destination

04 Sector growth

- Promote entertainment tourism and marquee events
- Drive sector growth, innovation and employment generation



INSTITUTIONAL FRAMEWORK

State Event Facilitation Cell

SWCS ROLLOUT

Three-step digital pathway

MANDATE	Coordinate approvals and industry engagement; develop venues, promote tourism and operate the SWCS.	
GOVERNANCE	State Level Monitoring Committee and relevant Competent Authorities.	
DATA ASSETS	— State Event Calendar — Venue Registry — Event Impact Database	— Economic Impact Reports — Approval Dashboard

- 01

INTERIM STATE ROUTE

Use MIB’s ICH portal until Maharashtra’s SWCS launches.
- 02

SYSTEM CONNECTION

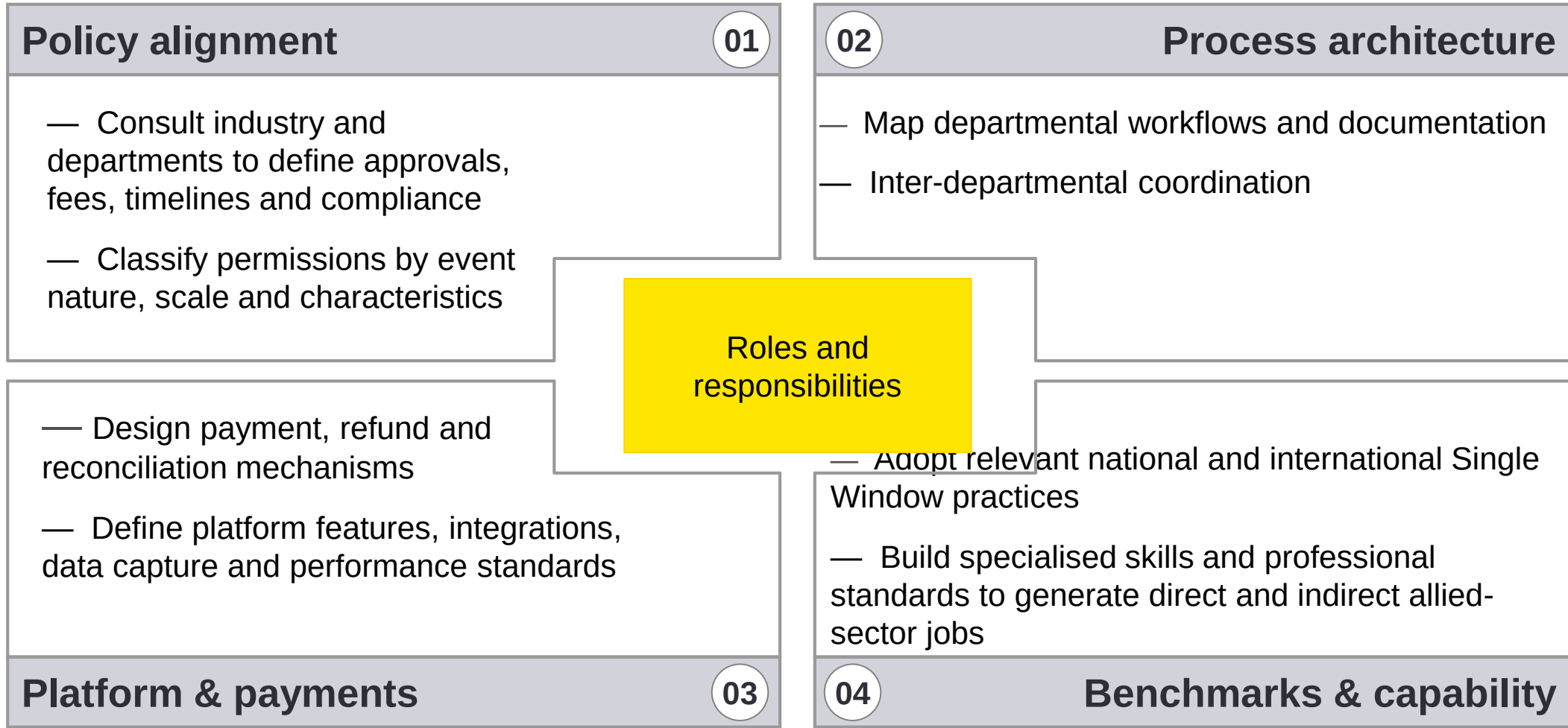
DGIPR connects departmental and local systems for end-to-end processing, tracking and monitoring.
- 03

FUTURE STATE

State SWCS will be built from operational feedback, then integrated with ICH.

DGIPR sustains the SWCS through four operating roles

SWCS CONTINUITY MECHANISM: Roles and Responsibilities of DGIPR



Existing licences remain mandatory

CHAPTER III LIVE EVENT LICENSING FRAMEWORK: APPLICABLE LICENCES (1/3)



APPLICABLE LICENCES Requirements vary by event, venue and activity

01 Safety & mobility

POLICE (LAW & ORDER)

NOC; event permission; event details; loudspeaker and drone permissions

TRAFFIC POLICE

NOC; parking approval

FIRE SAFETY

NOC; venue layout

ELECTRICAL SAFETY

NOC; generator installation

02 Venue & jurisdiction

MUNICIPAL CORPORATION / GRAM PANCHAYAT

Jurisdictional NOC; venue, temporary structure and food-stall permissions; venue layout; waste-management compliance

EDUCATION / GARDEN

School-ground, park or garden permission

MAHARASHTRA MARITIME BOARD

Approval, where applicable

03 Event-specific clearances

EXCISE

Licence to serve or sell alcohol

FRRO

Foreign-artist clearance

ARCHAEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Approval for heritage-site events

MUSIC RIGHTS

IPRS, PPL, NOVEX and ISRA licences

From MEO

State Licenses



An organised,
audience-facing
event with one or
more qualifying
characteristics.

Examples: performances,
festivals, concerts, sports,
activations and public
celebrations.

QUALIFIES THROUGH ONE OR MORE OF SIX TESTS

01	AUDIENCE & PROGRAMME Public or invited audience	02	APPROVALS & SAFETY Permissions + safety controls
03	TEMPORARY PRODUCTION Stages, sound, lighting, power	04	VENUE Public or temporary venues
05	OPERATIONS & COMMERCE Providers, tickets, sponsors	06	MEDIA & PUBLIC IMPACT Broadcast, promotion, operations

BOUNDARY

Not included: ordinary private functions requiring no event-specific
production, permissions or dedicated safety.



CASE-SPECIFIC PERMISSIONS

PERMISSION	APPLIES WHEN	WHY IT REMAINS
01 Pest NOC	Venue pest-treatment proof is required, especially for closed venues	Confirms food-safety protection and valid venue treatment.
02 SWM permission	Waste requires segregation and collection.	Ensures dry/wet segregation and disposal through an approved vendor or municipal service.
03 Foreign artist clearance	A foreign artist performs; Home Department clearance applies.	Ensures oversight of foreign nationals; passport and valid visa are required.
04 Show Tax / Theatre Licence	Municipal permission for conducting public entertainment venues within PMC limits.	Maintains compliance with municipal safety, occupancy, sanitation, and local regulatory requirements.
05 Excise slips	Alcohol is served to patrons of legal drinking age.	Links eligible attendance to excise monitoring

PRINCIPLE **Require each permission only when the event, venue or activity creates the relevant regulatory need.**

Application Process and Composite fee structure

CHAPTER III LIVE EVENT LICENSING FRAMEWORK



APPLICATION PROCESS

Common Application Form

One primary interface for every live-event licence and permission.

- SUBMIT** All applications through the CAF on the SWCS.
- CAPTURE** Information and supporting documents required by the relevant Competent Authorities.

Single entry point • Consistent application data

COMPOSITE LICENCE FEE

DGIPR-notified fee structure

- STANDARD** DGIPR determines and notifies applicable approval and licence fees as State Nodal Agency.
- INPUTS** Based on recommendations from Competent Authorities, including State Level Monitoring Committee members. The determination is final.
- TATKAL
(3 days processing)** An additional notified fee applies only when expedited processing is selected



INSPECTION MECHANISM

24

HOURS BEFORE
Event readiness complete

COMPLETE	Technical rehearsals, sound checks, safety demonstrations and other preparatory activities.
UPDATE	Inspection report and completion status recorded on the SWCS in real time.
EVIDENCE	Duly uploaded photographs of the inspected site.

PRE-APPROVED VENUES

No repeated event-level inspection

Relief applies when the event layout matches the pre-approved configuration.

EXEMPT	Repeat physical inspection and separate NOCs.
--------	---

RENEW	2×	PER YEAR Bi-annual venue inspection
-------	----	--

Venue conformity is the condition for continued relief.



STATE LEVEL MONITORING COMMITTEE

Constituted for SWCS governance and coordination

COMPOSITION

01	Chairperson	Principal Secretary & DG, Information and Public Relations; State Nodal Officer.
02	MIB representation	MIB SWCS Nodal Officers.
03	Member Secretary	Deputy Director-level or above representative of the Competent Authority handling the delayed application.
04	Industry voice	Event-organising institution stakeholders.

CORE MANDATE

IMPLEMENT	Implement and monitor the SWCS and Live Event governance framework.
COORDINATE	Coordinate inter-departmental approvals, permissions and compliance.
RESOLVE	Resolve delays, bottlenecks, operational issues and stakeholder grievances.
IMPROVE	Harmonise rules, standardise approvals and advance safety, tourism, investment and sector growth.

Committee for Single Window Clearance (Live Events)

CHAPTER IV: POWERS AND FUNCTIONS OF THE MONITORING COMMITTEE: COMPOSITION



Chairperson	Members	Invited Members
Principal Secretary and Director General, Information and Public Relation, GAD	Police Department- Maharashtra & Mumbai – Additional Director General of Police (Law & Order), Additional Director General of Police (Traffic), Joint Commissioner of Police, Mumbai Police Information Technology Department- Director, Information Technology Municipal Corporation of Greater Mumbai- Additional Municipal Commissioner / Deputy Commissioner District Collector & Magistrate, Mumbai City & Suburban- Additional District Magistrate Archaeological Survey of India (GoI)- Director Maharashtra Fire & Emergency Services- Director Directorate of Archaeology & Museums- Director Public Works Department (PWD) – Chief Engineer BEST Undertaking- Chief Engineer (Electrical) State Excise Department – Commissioner/ Joint Commissioner Directorate of Cultural Affairs- Director Revenue & Forest Department – Joint Secretary & Deputy Secretary Rural Development Department- Joint Secretary & Deputy Secretary Energy Department- Joint Secretary & Deputy Secretary Administrative Innovation, Excellence & Good Governance (GAD) - Joint Secretary & Deputy Secretary Environment & Climate Change Department- Joint Secretary & Deputy Secretary Public Health Department- Joint Secretary & Deputy Secretary Information & Public Relations- Director (Information) (Administration, Director Information) (News & Public Relations), Deputy Director (News), Senior Assistant Director (Documentary)	Event Organising institutions (as required)



01 Police & drones

Attendance, timings, VIP presence, venue, organiser and jurisdiction details; authorised drone operators, safeguards and police coordination.

02 Traffic & private land

Event, venue, timing, attendance and brief details for traffic planning; landowner NOC where applicable.

03 Municipal permissions

Pest control, waste management, public health, hygiene, food safety and protection of municipal property.

04 Fire & temporary structures

Separate rules by venue type; access, exits, seating, fire-resistant materials, cooking and stalls, extinguishers and fire marshals.

05 Electrical safety

Load and temporary-supply assessment, licensed contractors, inspection and safe wiring; layout, SLD, test reports, load and licence documents.

06 Excise

Temporary One Day Function Licence, premises registration, plus solvency certificate or bank guarantee requirements.

Maharashtra is advancing three building blocks for live events



STATE INITIATIVES | LIVE EVENTS

Infrastructure, industry-ready skills and a simpler path to approvals

01

GREENFIELD VENUE

Evaluating viable models to develop a purpose-built live-events venue.

CURRENT FOCUS

Identify the delivery and operating model, including DBOT/DBFOT/BOO, for efficient development and sustainable operations.

02

LIVE-EVENT SKILLS

Working with MSSU to design courses for the live-events sector.

NEXT STEP

Conduct industry consultations to identify on-ground skill requirements and develop courses.

03

SINGLE-WINDOW CLEARANCE

Exploring a simpler, coordinated approval experience.

UNDER REVIEW

State-owned single-window clearance system



Thank You!



भारतीय जन संचार संस्थान
**Indian Institute of Mass
Communication**
(Deemed to be University)



Annexure-D

SHAPING INDIA'S EXPERIENCE ECONOMY THROUGH EVENT EDUCATION



भारतीय जन संचार संस्थान
Indian Institute of Mass
Communication
(Deemed to be University)



ABOUT IIMC



- Premier institute for mass communication education, training and research in India
- Consistently ranked among the top institutions in evaluation studies by media and professional bodies, year after year
- Inaugurated on August 17, 1965
- Offers **8 PG Diploma programmes**, spanning regional-language journalism (English, Hindi, Odia, Marathi, Urdu, Malayalam) and specialized tracks in Advertising & PR and Radio & TV Journalism
- Offers **6 Master's programmes** covering emerging and strategic domains — Media & Business Studies, New Media Communications, Media & Communication Governance, Strategic Communication, Health Communication, and Corporate Communication & Brand Management
- **14 specialized courses** in total, reflecting a portfolio built to match evolving industry needs and expanded into doctoral education with the **launch of the PhD programme this year.**

MESC & EEMA: OUR PARTNERS

MESC (Media & Entertainment Skills Council)

- Not-for-profit skill council set up in 2012 under the Ministry of Skill Development & Entrepreneurship
- Supported by FICCI and NSDC; an NCVET-awarding body
- Sets national skill standards across 12 M&E sub-sectors, including Live Performance / Event Management
- Runs NSQF certification, MECAT assessment, and the Creative Warriors and Vidyadaan platforms
- 7,00,000+ trainings, 5000+ certified trainers, 350+ affiliated universities and colleges

EEMA (Event & Entertainment Management Association)

- India's apex non-profit industry body for events, experiential marketing, entertainment, MICE and weddings.
- Unites event and sports management firms, brand activation agencies, MICE and wedding planners, and artist management companies on one platform
- Represents the industry before government, statutory and licensing bodies
- Offers students internships, live event access, masterclasses, the Eduposium bootcamp and placements



A formal MoU was signed between IIMC and MESC on 29th September, 2026

MoU: IIMC & EEMA



भारतीय जन संचार संस्थान
Indian Institute of Mass
Communication
(Deemed to be University)





DEVELOPMENT SO FAR....

- 1. MoU Signed:** A formal IIMC–MESC partnership was signed on 29 September 2026.
- 2. Programme Designed:** A two-semester, 43-credit Event Management Diploma course matrix has been drafted.
- 3. MESC Built In:** NSQF certification, MECAT, Creative Warriors and upskilling are included in the final semester.
- 4. Elective Slots Mapped:** Existing elective baskets across MA and PG Diploma programmes have been identified for the event management elective.
- 5. Roadmap Set:** A three-stage activation plan is in place: elective, then diploma, then short-term certificates.

10 Programmes with live-event content

20+ Papers covering events & live media

5 Language journalism diplomas on board

MA PROGRAMMES

MA Media Business Studies Live events as an M&E segment; sports, hybrid & virtual events 4	MA Strategic Communication Event management in PR & corporate communication 1	MA New Media Communications Live photo events, comics exhibition, startup fair 9	MA Corporate Comm. & Brand Management Event planning, crisis management & evaluation 1
---	--	---	---

PG DIPLOMAS

Advertising & PR Live events development 1	English Journalism Event management & experiential comm. 1	Hindi Journalism Live media coverage & event management 2	Malayalam Journalism Corporate, cultural & hybrid events 1	Marathi Journalism Planning, budgeting & risk management 1	Odia Journalism Event management & experiential comm. 1
---	---	--	---	---	--

ALREADY ON THE GROUND

Live photo events	Grassroot comics exhibition	Startup fair participation	Creator-led live campaign	AR/VR studio visit	Design thinking challenge
-------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------	---------------------------



HOW MESC ENABLES EXPERIENTIAL LEARNING IN EVENT MANAGEMENT?

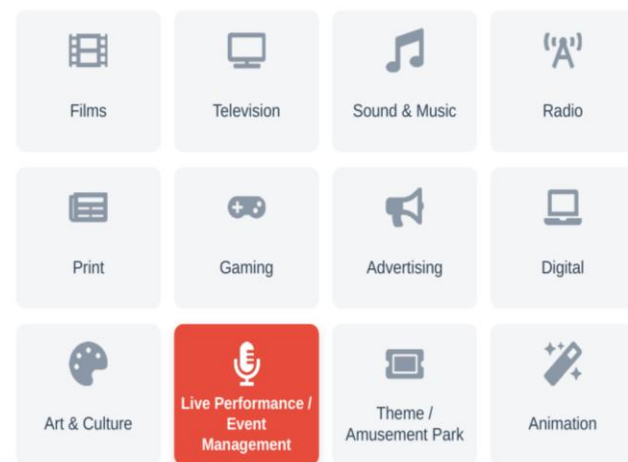
- 1. **Recognized domain:** Event Management is one of MESC's 12 M&E sub-sectors.
- 2. **Defined competencies:** Qualification Packs benchmark hands-on learning in a jointly reviewed curriculum.
- 3. **Assessed & certified:** MECAT tests applied skills; NSQF certifies them nationally.
- 4. **Expert & global exposure:** Creative Warriors workshops, plus WorldSkills-aligned training via AWSITC and IICS.
- 5. **Scale & reach:** 7 lakh+ trainings and 5000+ certified trainers support practice across IIMC's regional centres.
- 6. **Career-ready & lifelong:** Industry-validated certification, ongoing upskilling, and the IIMC–MESC MoU (Sept 2026).



A continuous loop: upskilling feeds back into new job-role standards and fresh practice

THE LEARNER'S JOURNEY: WHERE MESC COMES IN

Experiential learning runs throughout; MESC standards frame it and MESC certification closes it



WHY IT MATTERS

- Event skills sit inside a national, occupation-mapped framework, not as an add-on.
- Qualification Packs describe what an event professional must be able to do.
- That gives the 70% experiential component a clear benchmark.



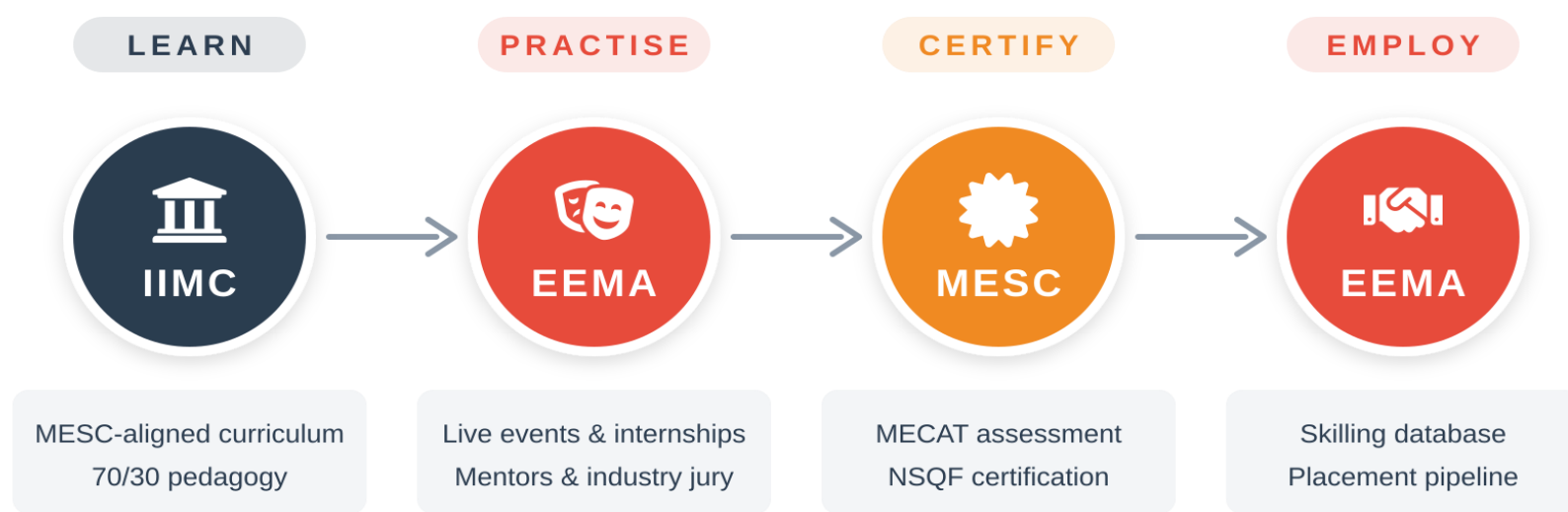
ONE YEAR. INDUSTRY READY



- **Regulatory Fit:** Two semesters, 43 credits, meeting the UGC/NEP PG Diploma norm.
- **IIMC Model:** In line with IIMC's established one-year PG Diplomas.
- **Complete Curriculum:** Foundations, specialization and an internship in one year.
- **Industry Urgency:** Fast talent supply for a ₹196B market with a 65% skills gap.
- **Practice-Led:** 70% experiential learning across a full annual event cycle.
- **Accessible:** Lower cost and time for Tier 2 and Tier 3 learners.
- **Job-Ready:** NSQF and EEMA certification plus placement support within the year.



THE INDUSTRY BRIDGE: EEMA-MAKING MESC COUNT



EEMA frames MESC certification: practice before it, jobs after it

1. **Shapes the curriculum:** Brings real industry needs into the MESC-aligned syllabus.
2. **Provides the practice:** Live events and internships build the skills MESC certifies.
3. **Validates skills:** Its industry jury works alongside MESC's MECAT assessment.
4. **Gives certification value:** EEMA recognition makes NSQF certification count with employers.
5. **Creates jobs:** A skilling database and placement pipeline for certified graduates.

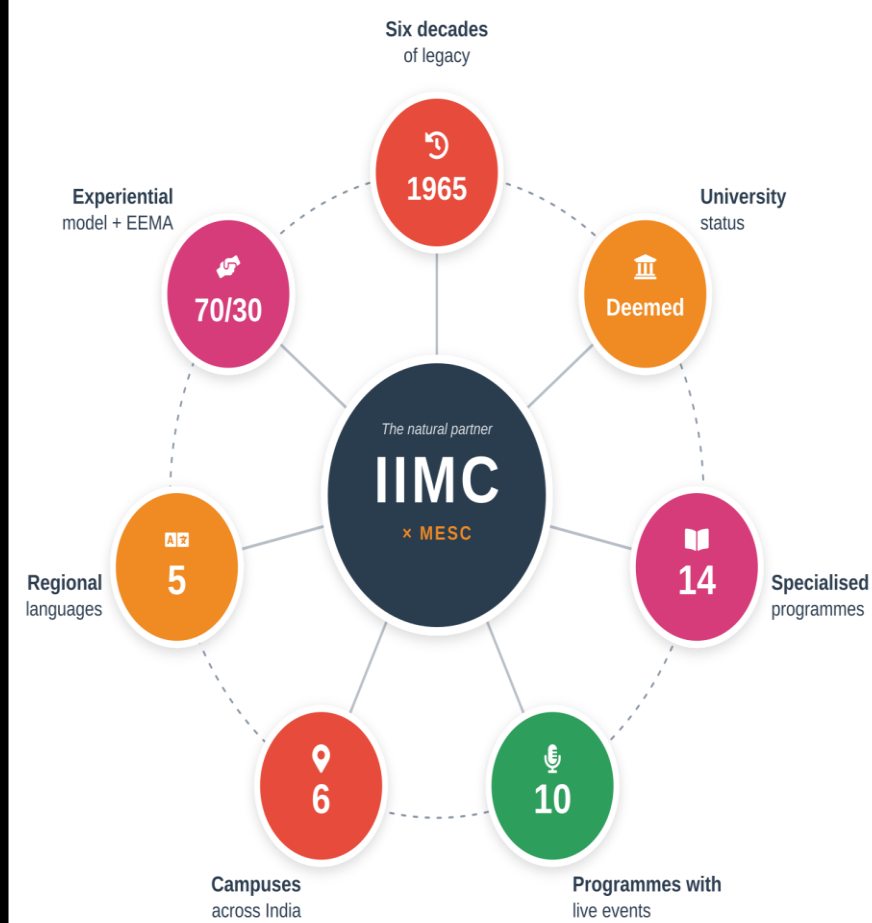


IIMC

BUILT FOR SKILLING, READY TO SCALE

WHY IIMC FOR MESC?

1. **Proven Legacy:** Six decades in media education since 1965, consistently ranked among India's top institutions.
2. **University Status:** A Deemed-to-be University able to award recognized diplomas, with a PhD programme now launched.
3. **Full M&E Spectrum:** 14 specialized programmes across journalism, advertising, PR, new media, and corporate and strategic communication.
4. **Live Events Already Embedded:** 10 programmes and 20+ papers already cover events and live media.
5. **Pan-India Reach:** Six campuses in Delhi, J&K, Odisha, Maharashtra, Mizoram and Kerala, reaching Tier 2 and Tier 3 learners.
6. **Multilingual Delivery:** Journalism programmes in Hindi, Urdu, Odia, Marathi and Malayalam enable skilling in regional languages.
7. **Industry-Ready Model:** 70/30 experiential pedagogy, backed by an EEMA partnership for live events and placements.





भारतीय जन संचार संस्थान
Indian Institute of Mass
Communication
(Deemed to be University)



IIMC × MESC × EEMA

THANK YOU

Together, shaping the architects of tomorrow's experiences

